



CH/95
9/7/95

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216]
No. 216]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 27, 1985/वैशाख 7, 1907
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 27, 1985/VAISAKHA 7, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रयुक्त होगी।

(आर्थिक कार्य विभाग)

2. राष्ट्रीय बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम,
1970 में—

(बैंकिंग प्रभाग)

(क) खंड 13 का लोअर किया जाएगा;

ब्रह्मसूचनाएँ

(ख) (i) खंड 14 को उक्ते उपखंड (1) के
रूप में पुनर्मध्याहित किया जाएगा और दाता प्र
पुनर्मध्याहित उपखंड (1) में मे “एमी अन्य”
शब्दों का नोट किया जाएगा;

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1985

(ii) इस प्रज्ञार पुनर्संबंधान्वित उपखंड (1) के पश्चात्
निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा,
अर्थात् :—

“(2) उपखंड (1) के अधीन गठित किसी
समिति को बोर्ड, किसी भी समय जब वह
ठीक समझे, पुनर्गठित कर सकता है।”

का आ. 368 (अ).—केन्द्रीय मरकार, वैद्यारी कम्पनी
(उपक्रमों का अर्जन और अन्वयण) अधिनियम, 1970
(1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त
णक्षियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने परामर्श
करने के पश्चात् राष्ट्रीय बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध)*
स्कीम, 1970 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित
स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का मंदिरपत्र नाम राष्ट्रीय बैंक
(प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) स्कीम, 1985 है।

(ग) खंड 16 के उपखंड (4) का लोप किया जाएगा;
 (घ) खंड 18 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“18. बोर्ड के अधिकारों के बिना संकल्प का विधिमान्य होना—
 बोर्ड के सदस्यों की बहुसंख्या द्वारा हस्ताक्षरित लिखित संकल्प विधिमान्य और प्रभावकारी होगा और वह बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित संकल्प समझा जाएगा जिस दिन संकल्प पर अतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किए हैं;

परन्तु पूर्वोक्त रूप में पारित कोई संकल्प, बोर्ड के अगले अधिकारों में रखा जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि विसम्मति प्रकाट करने वाला कोई सदस्य लिखित रूप में यह अपेक्षा करता है कि इस प्रदार पारित कोई संकल्प बोर्ड के अधिकारों में रखा जाए तो संकल्प यथापूर्वोक्त रूप में तब तक विधिमान्य और प्रभावकारी नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह ऐसे अधिकारों में पारित नहीं हो जाता ।” ।

[सं. एफ. 4/1/84-बी. ओ.-I (1)]

*मूल स्कीम अधिसूचना सं. का. आ. 3793, तारीख 16 नवम्बर, 1970 के अधीन प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसका संशोधन किया गया :—

क्रम सं.	का. आ. सं.	तारीख
1.	67(अ)	17-11-71
2.	192(अ)	15-3-72
3.	575(अ)	4-9-72
4.	651(अ)	25-9-72
5.	715(अ)	16-11-72
6.	3467	19-11-73
7.	1992	16-6-75
8.	1088	18-2-76
9.	421(अ)	21-6-76
10.	888(अ)	11-11-80
11.	346(अ)	30-4-83
12.	144(अ)	1-3-84

MINISTRY OF FINANCE
 (Department of Economic Affairs)
 (Banking Division)
 NOTIFICATIONS
 New Delhi, the 27th April, 1985

S.O. 368(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank

of India hereby makes the following scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme,* 1970, namely :—

1. (1) This scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme 1985.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

1. In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970,—

(a) clause 13 shall be omitted;
 (b) (i) clause 14 shall be renumbered as sub-clause (1) thereof and in sub-clause (1) as so renumbered, the words “such other” shall be omitted;
 (ii) after sub-clause (1) as so renumbered, the following sub-clause shall be inserted, namely :—
 “(2) Any committee constituted under sub-clause (1) may be re-constituted by the Board at any time it thinks fit.”
 (c) sub-clause (4) of clause 16 shall be omitted;
 (d) for clause 18, the following clause shall be substituted, namely :—

“18. Resolution without meeting of the Board valid.—A resolution in writing signed by the majority of the members of the Board shall be valid and effectual and shall be deemed to be the resolution passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the resolution.

Provided that any resolution passed as aforesaid shall be placed before the next meeting of the Board :

Provided further that if any dissenting member requires in writing that any resolution so passed shall be placed before a meeting of the Board, the resolution shall not be deemed to be valid and effectual as aforesaid unless the same is passed at such meeting.”.

[No. F. 4/1/84-B.O.-I(1)]

*The Principal Scheme was published vide notification No. S.O. 3793, dated 16th November, 1970 and subsequently amended vide the following notifications :—

S.	S.O. No.	Date
1.	67(E)	17-11-71
2.	192(E)	15-3-72
3.	575(E)	4-9-72
4.	651(E)	25-9-72
5.	715(E)	16-11-72
6.	3467	19-11-73
7.	1992	16-6-75
8.	1088	18-2-76
9.	421(E)	21-6-76
10.	888(E)	11-11-80
11.	346(E)	30-4-83
12.	144(E)	1-3-84

का. आ. 369(ज).—केन्द्रीय सरकार, बैंकशारी द्वारा द्वारा (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक में पश्चात् डरने के पश्चात्, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध)* स्कीम, 1980 का और संशोधन डरने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का मंभिलन नाम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन, स्कीम, 1985 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
2. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 में,—

(क) खंड 13 का लोप किया जाएगा;

(ख) (i) खंड 14 को उसके उपबंध (1) के स्तर में पुनर्संचयांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संचयांकित उपखंड (1) में से “ऐसी अन्य” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) इस प्रकार पुनर्संचयांकित उपखण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(2) उपबंध (1) के अधीन गठित हिसी समिति को बोर्ड, हिसी भी समय जब वह शीक समझे, पुनर्गठित कर सकता है।”;

(ग) खंड 15 के उपखंड (4) का लोप किया जाएगा;

(घ) खंड 17 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“17 बोर्ड के अधिकारों के बिना संकल्प का विधिमान्य होना—”

बोर्ड के सदस्यों की बहुसंख्या द्वारा हस्ताक्षरित लिखित संकल्प विधिमान्य और प्रभावशारी होगा और वह बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित संकल्प समझा जाएगा जिस दिन संकल्प पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हैं।

परन्तु पूर्वोक्त रूप में पारित कोई संकल्प, बोर्ड के अगले अधिकारों में रखा जाएगा :

परन्तु यह और हि यदि विप्रमति प्रलिप्त नहरने वाला कोई नदस्य लिखित रूप में यह अनेका करता है तो इन प्रकार पारित कोई संकल्प बोर्ड के अधिकारों में रखा जाए तो संकल्प यथापूर्वोक्त रूप में नव तरह विधिमान्य और प्रभावशारी नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह ऐसे अधिकारों में पारित नहीं हो जाता।”।

[सं. एफ. 4/1/84-बी. ओ.-I (2)]
बी. के, विवल, संयुक्त सचिव

*टिप्पणी : मूल स्कीम, अधिसूचना सं. का. आ. 875(अ) तारीख 4 नवम्बर, 1980 द्वारा प्रकाशित की गई और तत्परतात् उत्तर संशोधन क्रमशः अधिसूचना सं. का. आ. 345(अ) तारीख 30-4-1983 और का. आ. 145(अ) तारीख 1-3-1984 द्वारा दिया गया।

S.O. 369(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, (40 of 1980), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) *Scheme, 1980, namely:—

1. (1) This scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme, 1985.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980,—

(a) clause 13 shall be omitted;

(b) (i) clause 14 shall be renumbered as sub-clause (1) thereof and in sub-clause (1) as so renumbered, the words “such other” shall be omitted;

(ii) after sub-clause (1) as so renumbered, the following sub-clause shall be inserted, namely:—

“(2) Any Committee constituted under sub-clause (1) may be re-constituted by the Board at any time it thinks fit.”;

(c) sub-clause(4) of the clause 15 shall be omitted;

(d) for clause 17, the following clause shall be substituted, namely:—

“17. Resolution without meeting of the Board valid.—A resolution in writing signed by the majority of the members of the Board shall be valid and effectual and shall be deemed to be the resolution passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the resolution :

Provided that any resolution passed as aforesaid shall be placed before the next meeting of the Board :

Provided further that if any dissenting member requires in writing that any resolution so passed shall be placed before a meeting of the Board, the resolution shall not be deemed to be valid and effectual as aforesaid unless the same is passed at such meeting.”.

[No. F. 4/1/84-B.O.-I(2)]

V.K. SIBAL, Jr. Secy.

*The Principal Scheme was published vide Notification No. S.O.875 (E), dated 4th November, 1980 and subsequently amended vide notifications No. S.O. 345 (E) dated 30.4.1983 and S.O. 145 (E) dated 1.3.1984 respectively.

